The details of agricultural production as well as public sector investment (both at 1980-81 prices) during the Eighth Plan year-wise are given below:

(Rs. in crore)

Year	GDP from Agriculture	Public sector Investment in Agriculture
1992-93	63327	1061
1993-94	65762	1153
1994-95	69206	1316
1995-96	66863	1268
1996-97	72362	1132

(c) Ninth Plan has recognised the importance of higher investment in agriculture and rural infrastructure for increasing agricultural growth. The Plan envisages to increase public investment for infrastructure like irrigation, electricity, agricultural research, roads and communications.

सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों के लिए कार्य योजना

2666. **श्री राजूभाई ए० परमार:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों के विकास के लिए कोई कार्य योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम नामक एक दीर्घकालीक क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है ताकि सूखे से प्रभावित क्षेत्रों का विकास किया जा सके। यह कार्यक्रम एक तकनीकी समिति की सिफारिशों पर सूखा प्रभावति क्षेत्रों के रूप में अभिज्ञात किए गए 155 जिलों के 947 ब्लाकों में चलाया जा रहा है। पनधारा आधार पर 500 हैक्टेयर के औसत क्षेत्र वाली परियोजनाओं का कार्यान्वयन करके इन क्षेत्रों का एकीकृत विकास किया जाता है।

सब्जियों के बीज उत्पादन हेतु सहायता

2667. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में सब्जियों के बीज उत्पादन व वितरण हेतु निर्धारित वित्तीय व वास्तविक लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये थे; तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत सरकार द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना में बीज उत्पादन व वितरण का कितना वित्तीय व वास्तविक लक्ष्य तय किया गया है; इस संबंध में वर्ष 1999-2000 के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है; और

(ग) राजस्थान में बीजों के उत्पादन व वितरण के लिए वर्ष 1999-2000 के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है तथा इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि आवंटित करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) विभिन्न फसलों, जिनमें सब्जी-फसलें शामिल हैं, के बीजों के उत्पादन और वितरण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। इसलिए, भारत सरकार विभिन्न फसलों, जिनमें सब्जी की फसलें शामिल हैं, के उत्पादन और वितरण के लिये कोई वित्तीय तथा भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है।

सब्जी बीज फसलों के प्रमाणीकरण के तहत उपलब्धता और क्षेत्र में वृद्धि करने के लिये 1995-96 में महत्वपूर्ण चयनित सब्जी फसलों के प्रमाणित बीज उत्पादन को सरल व कारगर बनाने के लिये एक केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम आरंभ की गई थी। 1998-99 से इस स्कीम में आधारी बीज उत्पादन तथा सब्जी बीजों के प्रसंस्करण और पैकेजिंग के लिये बुनियादी ढांचे की सुविधाओं के सृजन के घटक शामिल करके इसे सुधारा गया है। इस स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकारों को अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करनी पड़ती है जिसमें भौतिक और वित्तीय लक्ष्य देने होते हैं, ताकि तदनुसार धन निर्मुक्त किया जा सके। भारत सरकार इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिये प्रशासनिक अनुमोदन जारी करने के लिये सैद्धांतिक, भौतिक और वित्तीय लक्ष्य

निर्धारित करती है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तथा उनके मुकाबले उपलब्धियां और नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिये भौतिक और वित्तीय लक्ष्य इस प्रकार हैं:—

आठवीं पंच वर्षीय योजना

वर्ष	भौतिक (मात्रा क्विंटल में)		वित्तीय (रुपये लाखो में)	
	लक्ष्य	उपलब्धि (सब्जी बीज उत्पादन)	लक्ष्य	उपलब्धि (निर्मुक्त धन-राशि)
1995-96	21260	*10598.00	25.00	27.43
1996-97	31891	*7021.19	51.00	क236.40

*विभिन्न कार्यान्वयनक राज्यों से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

क धन की निर्मुक्ति राज्यों के साथ हुई चर्चा के आधार पर तथा उनकी कार्य योजना के अनुसार की गई।

भौतिक-मात्रा लाख क्विंटल में
वित्तीय- रुपये लाखों में

नौवीं पंचवर्षीय योजना

घटक	1997-98 के लक्ष्य		नौवीं योजना के लक्ष्य (1998-99 से 2001) 2002 के चार वर्षों की योजना		1999-2000 के लक्ष्य	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
(1) आधारी बीज उत्पादन	—	—	0.99	74.23	0.03	19.46
(2) प्रमाणित बीज उत्पादन	0.23	88.00	1.68	1515.42	0.44	358.55

राज्य सरकारों से, जिनमें राजस्थान शामिल है, अपनी कार्य योजनाएं अर्थात 1999-2000 के लिये भौतिक और वित्तीय लक्ष्य भेजने के लिये कहा गया है ताकि प्रशासन अनुमोदन जारी करते समय उन्हे शामिल किया जा सके। अभी तक राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

Deep Sea Fishing Policy

2668. SHRI P. PRABHAKAR REDDY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to formulate a new deep sea fishing policy to tap the potential for marine fisheries;

(b) whether the policy, if introduced, would lead to the lifting of ban, currently in force, on issuing licenses to deep sea fishing vessles; and

(c) if so, what steps are being adopted to protect the interest of small and medium fishermen and their fishing rights in the coastal areas?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) to (c) Action has been initiated to constitute an Expert Committee to formulate a